जागरण

# डेलायट इंडिया बनाएगी यूपी को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप, कंपनी को पांच महीने का मिला वक्त

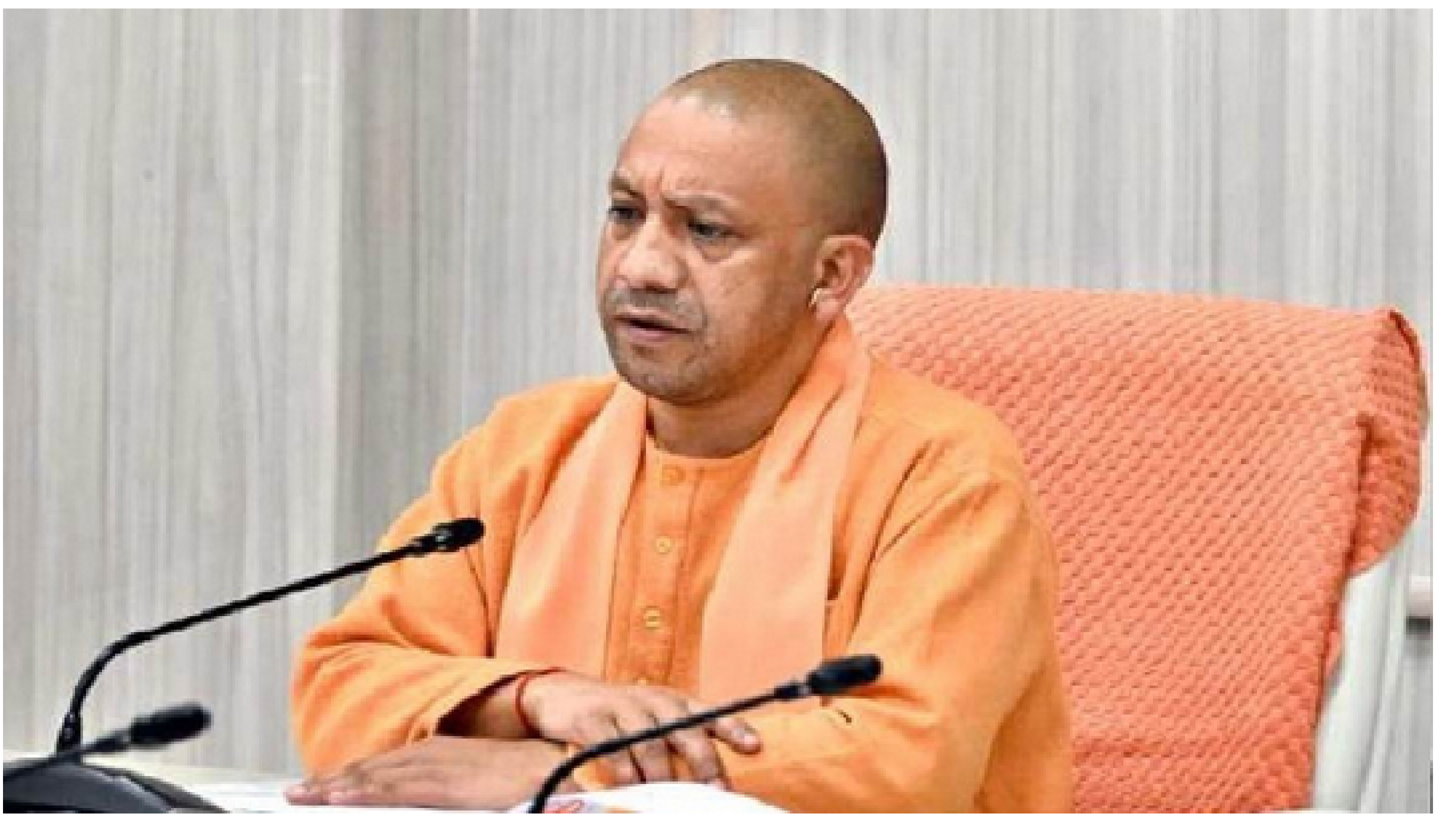

UP Cabinet Decision कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कंसल्टेंट चयन के लिए 15 मार्च को इच्छुक कंपनियों व कंसल्टेंट से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इसमें सात संस्थाओं से निविदाएं प्राप्त हुई थीं। उच्चतम कंपोजिट स्कोर पाने वाली डेलायट इंडिया को कंसल्टेंट चुना गया है।

UP Cabinet Decision: लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप कंसल्टेंट के तौर पर डेलायट इंडिया तैयार करेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति की ओर से बिड प्रक्रिया के आधार पर किये गए कंसल्टेंट के चयन पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगी।

योगी कैबिनेट के निर्णय के बारे में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कंसल्टेंट चयन के लिए 15 मार्च को इच्छुक कंपनियों व कंसल्टेंट से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इसमें सात संस्थाओं से निविदाएं प्राप्त हुई थीं। इन संस्थाओं में नाबार्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्वेस्ट इंडिया, डा.राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डेलाइट इंडिया, ग्रांट थार्नटन इंडिया, बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और आइसार्क शामिल थे।

25 मई को तकनीकी निविदा खोली गई जिसमें तीन कंपनियां वित्तीय निविदा के लिए चुनी गई थीं। इनमें बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ग्रांट थार्नटन इंडिया और डेलाइट इंडिया शामिल थीं। तकनीकी और वित्तीय निविदा के आधार पर 81.61 का उच्चतम कंपोजिट स्कोर पाने वाली डेलायट इंडिया को कंसल्टेंट चुना गया है। डेलायट ने 164 करोड़ रुपये की बिड धनराशि कोट की थी जिसे बातचीत के बाद 120 करोड़ रुपये करने पर वह सहमत हुई।

गौरतलब है कि वित्तीय निविदा में शामिल बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने 120 करोड़ रुपये तथा ग्रांट एंड थार्नटन ने 39.6 करोड़ रुपये बिड धनराशि कोट की थी। तकनीकी और वित्तीय निविदा के आधार पर ग्रांट एंड थार्नटन का कंपोजिट स्कोर 76 रहा, वहीं बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को 67.4 अंक मिले।

सचिव नियोजन आलोक कुमार ने बताया कि आरएफपी की शर्तों में तकनीकी निविदा के मूल्यांकन को 80 प्रतिशत और वित्तीय निविदा के मूल्यांकन को 20 प्रतिशत वेटेज देना शामिल था। इसी आधार पर डेलायट इंडिया को कंसल्टेंट चुना गया। अनुबंध के बाद कंसल्टेंट को पांच महीने में प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप तैयार करना होगा।